छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील संख्या 424/2005

निर्णय सुरक्षित: 15-10-2019
निर्णय घोषित : 24-10-2019

1. अफजल अली, पुत्र स्व. रहमत अली, उम्र 35 वर्ष।

2. अशरफ अली, पुत्र स्वर्गीय रहमत अली, उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम बरवाही, व्यवसाय कृषक, तहसील पाल, जिला – सरगुजा (छ.ग.)

3. श्रीमती नूरजहाँ (मृत और हटाया गया)

(वादीगण)

-----अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. अमरुद्दीन अंसारी (मृत) विधिक वरिसान के माध्यम से

(1) जैबुन, पत्नी स्व. अमरुद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 60 वर्ष,

(2) उमत रसूल, पुत्र स्व. अमरुद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 45 वर्ष,

(3) आबिद, पुत्र स्व. अमरुद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 42 वर्ष,

(4) आसिक अंसारी, पुत्र अमरुद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 39 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम दोलांगी, पोस्ट दोलांगी, जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर (छ.ग.)

2. वोलायत अंसारी, वाजिद अली अंसारी के पुत्र, उम्र 46 वर्ष।

3. ताहिर हुसैन, वाजिद अंसारी के पुत्र, उम्र 40 वर्ष।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3, निवासी गांव दोलांगी, व्यवसाय कृषक, तहसील पाल, जिला सरगुजा (छ.ग.)

4. श्रीमती बेगम उर्फ आमना खातून, पुत्री अब्दुल रज़्ज़ाक, उम्र लगभग 45 वर्ष,

5. श्रीमती सेयारा खातून, पुत्री अब्दुल रज़्ज़ाक, उम्र लगभग 35 वर्ष।

प्रतिवादी संख्या 4 और 5 निवासी ग्राम जयनगर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

6. छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा सरगुजा कलेक्टर, अंबिकापुर (छ.ग.)

(प्रतिवादीगण)
−−प्रत्युत्तरकर्ता

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री सुशील दुबे और श्री अमन उपाध्याय अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विधिक वारिसनो की ओर से: −
डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अश्विन पणिक्कर, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 6/राज्य की ओर से: −
श्री संजीव कुमार अग्रवाल, पैनल वकील।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल
सी.ए.वी. निर्णय

1. यह द्वितीय अपील, वादीगण/अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्नों को प्रस्तुत करते हुए सुनवाई हेतु स्वीकार की गई है:

i) "क्या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष न्यायसंगत था कि चूंकि डिक्री धारक ने विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपर्याप्त न्याय शुल्क जमा नहीं किया, इसलिए डिक्री निष्पादन योग्य नहीं रह जाती, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि अपर्याप्त न्याय शुल्क वादी/डिक्री धारक द्वारा विचारण न्यायालय की अनुमति से जमा की गई है?"
ii) "क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि प्राङ् न्याय के सिद्धांत के आधार पर वर्तमान वाद विचारणीय नहीं है, जबकि यह प्रमाणित नहीं किया गया कि पूर्व वाद उन्ही पक्षकारों के मध्य और उसी अनुतोष के लिए प्रस्तुत किया गया था ? ”
iii) "क्या अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है की वाजिब दावा नामक दस्तावेज (प्र.पी.01), जिसके द्वारा पट्टा धारक अब्दुल रजाक ने वादीगण के पक्ष में अपना अधिकार त्याग दिया था, को केवल इस आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है कि उसके अभीप्रमाणित गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया गया, विशेष रूप से जब प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज का विरोध नहीं किया गया है?"

[सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को विचारण न्यायालय में उनकी स्थिति के अनुसार संबोधित किया जाएगा।]

2. तीन वादीगण ने स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ−साथ कहा गया कि वाद योग्य भूमि पहले सरगुजा राज्य में मनवर भूमि थी, जो सरगुजा राज्य के महाराजा के पास थी और वादी संख्या 1 और 2 के पिता और वादी संख्या 3 के पति बरवाही गांव के गौटिया थे और गौटिया के रूप में उनकी सेवाओं के बदले,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अब्दुल रज़ाक के पक्ष में 14–10–1944 को गौटिया पट्टा प्र.पी–3 दिया गया था और अब्दुल रज़ाक, जो प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के पिता थे, ने अपने छोटे भाई रहमत अली – वादी संख्या 1 और 2 के पिता और वादी संख्या 3 के पति के पक्ष में 15–10–1952 को वाजिब दावा (प्र.पी–1) निष्पादित किया और उन्हें शांतिपूर्ण कब्जा दिया और राजस्व रिकॉर्ड में रहमत अली का नाम भी दर्ज किया गया क्रमांक 1 से 3 ने राजस्व अभिलेखों में अपने नाम परिवर्तित करवा लिए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने वाद की भूमि मरियम बीबी और प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 से खरीदी है, इस प्रकार, वादी स्वामित्व की घोषणा के हकदार हैं और 19–12–1986 की बिक्री विलेख अप्रभावी है।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया और इस तथ्य को स्वीकार किया कि वाद की जमीन को सरगुजा राज्य के महाराजा बहादुर द्वारा गौटिया पट्टा प्र.पी.3 के माध्यम से अब्दुल रज़ाक के पक्ष में आबंटित किया गया था। लेकिन रहमत अली के पक्ष में दिनांक 15–10–1952 के वाजिब दावा/बटवारा के तथ्य को खंडन किया और कब्जे को भी खंडन किया और एक तर्क दिया कि उन्होंने 19–12–1986 की बिक्री विलेख द्वारा वाद की भूमि खरीदी है और आगे प्राङ् न्याय का तर्क दिया कि व्यव्हार वाद संख्या 37अ/1996 (रहमत अली बनाम अमरुद्दीन और अन्य) को 26–2–1998 को खारिज कर दिया गया था और इसके विरुद्ध अपील भी दिनांक 1–7–1999 को खारिज कर दी गई थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. विचारण न्यायालय ने प्रकरण पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, प्राङ् न्याय के तर्क को नकार दिया और माना कि वादीगण 15–10–1952 के दस्तावेज प्र.पी. 1 के आधार पर वादभूमि के मालिक हैं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक को सरगुजा राज्य के महाराजा बहादुर द्वारा गौटिया पट्टा दिया गया था, जिसे राजस्व प्रकरण संख्या 6अ/1952–53 में उप आयुक्त के आदेश दिनांक 30–10–1954 द्वारा रियोती अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3/ संपत्ति के खरीदारों द्वारा अपील किए जाने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादीगण विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपर्याप्त न्याय शुल्क जमा नहीं किया और यह प्राङ् न्याय के सिद्धांत से प्रभावित है, जिसे विधि अनुसार सिद्ध नहीं किया गया है।

5. श्री सुशील दुबे, विद्वान अधिवक्ता, जो अपीलकर्ताओं/ वादी क्र. 1 और 2 के अधिवक्ता है, प्रस्तुत करेंगे कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निरस्त करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि वादीगण 28–10–2002 को डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद पहले ही न्याय शुल्क जमा कर चुके थे। व्यव्हार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 2 के तहत वाद खारिज कर दिया गया था और इसलिए आवेदन को अस्वीकार करने के बाद, नया वाद प्रस्तुत किया गया था जो समय पर था और बनाए रखने योग्य है। दस्तावेज़ प्र.पी.01 एक 30 साल पुराना दस्तावेज़ है और उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया था, इसलिए, इसकी प्रमाणिकता का अनुमान लगाया जाएगा और इस तरह, विवादित निर्णय और डिक्री को अलग रखा जाना चाहिए और अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

6. डॉ. एनके शुक्ला, जो की प्रतिवादी सं.1 के विधिक वरिसानो और प्रतिवादी सं.2 से 5 के अधिवक्ता है, ने यह तर्क प्रस्तुत किया की वादीगण ने विचारण न्यायालय के निर्णय की तारीख से 14 दिनों के बाद अपर्याप्त न्याय शुल्क जमा कर दी है और वाद को सही ढंग से प्राङ् न्याय द्वारा बाधित माना गया है और तीसरा, प्र.पी–1 के अनुसार अब्दुल रज्ज़ाक को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6(क) के मद्देनजर विशेष उत्तराधिकार हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था, जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है, सिवाय किसी उत्तराधिकारी के संपत्ति में सफल होने की संभावना, किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर किसी रिश्तेदार को विरासत प्राप्त होने की संभावना, या इसी तरह की प्रकृति की कोई अन्य संभावना के, ऐसे में अब्दुल रज्ज़ाक अपना रैयती अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, जो प्र.पी–1 के निष्पादन की तारीख 15–10–1952 को प्रदान नहीं किया गया था और जो वास्तव में 15–10–1952 को प्रदान किया गया था। 30–10–1954. अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी, प्र.पी. 1 एक पंजीकृत दस्तावेज़ नहीं है और इसलिए प्र.पी. 1 पर वादी को वाद से बाहर करने के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सही ढंग से भरोसा नहीं किया गया है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

<u>सारवान विधिक प्रश्न क्रमांक 01 का उत्तर:</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 16–10–2002 के निर्णय और डिक्री द्वारा निर्णय की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपर्याप्त न्याय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया था। वादीगण ने 21–10–2002 को निर्णय की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया, जो रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें 25–10–2002 को प्रदान किया गया और अंततः अपर्याप्त न्याय शुल्क का भुगतान 28–10–2002 को किया गया। यद्यपि वादीगण ने निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर से आवेदन किया, लेकिन आवेदन करने और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय अर्थात 21–10–2002, 22–10–2002, 23–10–2002, 24–10–2002 और 25–10–2002 – पांच दिन सात दिनों की अवधि की गणना के लिए बाहर होंगे और इसके अलावा विचारण न्यायालय ने स्वयं 19–10–2002 को डिक्री पर हस्ताक्षर किए। सामान्य व्यवहार में, निर्णय की प्रमाणित प्रति तब तक वितरित नहीं की जाती जब तक कि डिक्री पर आपत्तियां आमंत्रित न कर ली जाएं और उसके बाद डिक्री पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं। डिक्री पर 19–10–2002 को हस्ताक्षर किए गए और तुरंत, वादी ने 21–10–2002 को निर्णय की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था, निर्णय की प्रमाणित प्रति 25–10–2002 को वितरित की गई और 28–10–2002 को न्यायालय शुल्क जमा किया गया। अन्यथा भी, प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और न्यायालय ने वादी को बिना किसी विरोध और आपत्ति के 28–10–2002 को अपर्याप्त न्याय शुल्क जमा करने की अनुमति भी दी। इसलिए, इस पहलू में प्रथम अपीलीय न्यायालय का प्रतिकूल निष्कर्ष कायम नहीं रह सकता। तदनुसार, प्रथम सारवान विधि प्रश्न का उत्तर वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>सारवान विधिक प्रश्न क्रमांक 02 का उत्तर:</u>

9. चूंकि रहमत अली द्वारा प्रस्तुत पहला वाद – सिविल वाद संख्या 37 अ/1996 दिनांक 26–2–1998 को न्यायालय शुल्क का भुगतान न करने के कारण खारिज कर दिया गया था और बहाली के लिए आवेदन 1–7–1999 को खारिज कर दिया गया था, इसलिए, दूसरा वाद बाधित है। इसे देखते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना है कि वाद प्राङ् न्याय के सिद्धांत द्वारा बाधित था। सिविल वाद संख्या 37 अ/1996 में पारित दिनांक 26–2–1998 के आदेश पत्र की प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है, हालांकि इसे प्रदर्श के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी का वाद व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 2 के तहत प्रक्रिया शुल्क का भुगतान न

करने के कारण खारिज कर दिया गया था। व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 4 के तहत वादी के पास उपाय उपलब्ध है।

10. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 4 के तहत दूसरा वाद बाधित होगा?

11. व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 4 में निहित प्रावधान के आधार पर, जहां नियम 2 या नियम 3 के तहत एक वाद खारिज कर दिया जाता है, वादी (सीमा के कानून के अधीन) एक नया वाद ला सकता है; या वह खारिजी को निरस्त करने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि नियम 2 में संदर्भित ऐसी विफलता के लिए पर्याप्त कारण था, या उसकी अनुपस्थिति के लिए, जैसा भी प्रकरण हो, न्यायालय खारिजी को निरस्त करने का आदेश दे सकता है और वाद की कार्यवाही लिए एक तिथि नियत कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अब प्रश्न यह है कि क्या व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 4 के अंतर्गत निर्धारित दोनों उपचार एक–दुसरे के लिए परस्पर अनन्य है?

13. प्रिवी काउंसिल ने **भूदेव बनाम मुसम्मत बैकुंठी**[1] के प्रकरण में माना है कि व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 4 के तहत निर्धारित दो उपाय परस्पर अनन्य नहीं हैं और यदि पुनर्स्थापना के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया हो, नया वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे निम्नानुसार माना गया: –

> “1. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या दो उपचार जो एक वादी को दिए जाते हैं, जिसका वाद आदेश 9 नियम 2 या 3 के तहत खारिज कर दिया गया है, अर्थात्, एक नया वाद लाने का उपाय या खारिज किए जाने को निरस्त करने के लिए आवेदन करना, परस्पर अनन्य हैं। इस बिंदु पर, आदेश 9, नियम 4 के शब्द, धारा 99, अधिनियम XIV, 1882 के शब्दों के समान ही हैं। शब्द बहुत संतोषजनक नहीं हैं। "या" शब्द का उपयोग कई कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इस बात के बावजूद कि "या" शब्द का उपयोग किया जाता है और इस बात के बावजूद कि एक नया वाद लाने का उपाय पहले रखा जाता है और आदेश को निरस्त करने का उपाय दूसरे स्थान पर रखा जाता है, मेरी राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय सही है। मैं धारा के शब्दों में यह अर्थ नहीं समझ सकता कि जब कोई व्यक्ति, सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उसका वाद गलत तरीके से खारिज किया गया है, उस आदेश को

1 [1921]63 I.C. 239

निरस्त करने के लिए न्यायालय में आता है और सफल नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को यह दंड भुगतना पड़े की वह उन्ही तथ्यों पर एक और मुकदमा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं पा सके। नया वाद लाने के उपाय का चयन करने में वादी को नया न्याय शुल्क अदा करने की आवश्यकता होती है और स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति अपने वाद को पुनः स्थापित करवाने और नया न्याय शुल्क अदा करने से बचने का मौका लेना चाहेगा। ऐसा नहीं लगता कि विधानमंडल की यह मंशा थी कि यदि वह यह मौका लेता है, तो असफल होने की स्थिति में उसे अन्य सभी उपायों से वंचित कर दिया जाएगा। अपीलकर्ता के पक्ष में पूरी दलील व्यावहारिक रूप से केवल "या" शब्द के उपयोग पर टिकी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि अपीलकर्ता के तर्क का समर्थन करने के लिए उस तर्क में पर्याप्त बल है। इसलिए, मैं इस अपील को लागत के साथ खारिज करता हूं।”

14. **<u>भूदेव</u>** (सुप्रा) के प्रकरण में प्रिवी काउंसिल के द्वारा दिया गया निर्णय का अनुसरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **<u>गोविंद प्रसाद बनाम हर किशन और अन्य</u>**[2] के प्रकरण में किया। इसी तरह का प्रस्ताव अवध उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **<u>राजा कृष्ण पाल सिंह</u>**[3] के प्रकरण में रखा था जिसमें यह माना गया था कि व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 4 द्वारा निर्धारित दो उपचार परस्पर अनन्य नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वैसे भी, पहले वाद का निर्णय गुण–दोष के आधार पर नहीं किया गया था और **<u>श्योदान सिंह बनाम दरियाओ कुंवर</u>**[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि जहां पहले वाद में निर्णय गुण–दोष के आधार पर नहीं है, वहां व्य.प्र.सं. की धारा 11 में निहित सिद्धांत लागू नहीं होगा और निम्नानुसार माना गया: –

“किसी मामले को अंतिम रूप से सुना और निर्णय किया जा सके, इसके लिए पूर्व निर्णय में गुण–दोष के आधार पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां पूर्ववर्ती वाद को विचारण न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में, या वादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया हो, या पक्षकारों के अपूर्ण समावेश या अनुचित समावेश या विषयों के विविधता के कारण खारिज किया गया हो, या प्रकरण के गलत प्रारूपण के कारण खारिज किया गया हो, या किसी तकनीकी त्रुटि के कारण खारिज किया गया हो, या वादी द्वारा वसीयतनामा, प्रशासन के पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के कारण, जब वादी को डिक्री का हकदार बनाने के लिए विधि द्वारा इनकी आवश्यकता होती है, या लागतों के लिए सुरक्षा

2 (1929) AIR (Allahabad) 131
3 AIR 1937 Oudh 262
4 AIR 1966 SC 1322

प्रदान करने में विफलता के कारण, या अनुचित मूल्यांकन के आधार पर या कम मूल्यांकित वादपत्र पर अतिरिक्त न्याय शुल्क का भुगतान करने में विफलता के कारण या कार्रवाई के कारण के अभाव में या इस आधार पर कि यह समय से पहले है और अपील में खारिज किए जाने की पुष्टि हो गई है (यदि कोई हो) उस खारिजी आदेश की पुष्टि कर दी गई हो, तो निर्णय तथ्यात्मक मुद्दों पर आधारित न होने के कारण बाद के मुकदमे में वह निर्णय प्राङ् न्याय नहीं होगा।"

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि यद्यपि वादी का पहला वाद व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 2 के तहत प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के अभाव में खारिज कर दिया गया था और पुनर्स्थापना के लिए आवेदन भी खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए कानून के उपरोक्त सिद्धांत और दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने के मद्देनजर कि व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 4 के तहत उपलब्ध दो उपचार परस्पर अनन्य नहीं हैं, इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष कायम नहीं रह सकता है। तदनुसार सारवान विधिक प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सारवान विधिक प्रश्न क्रमांक 03 का उत्तरः

17. वाद की संपत्ति को 14-10-1944 को गौटीया पट्टा देकर अब्दुल रज़्ज़ाक के पक्ष में प्र.पी-3 के तहत निपटाया गया था और कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के पिता अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने छोटे भाई रहमत अली - वादी संख्या 1 और 2 के पिता और वादी संख्या 3 के पति के पक्ष में प्र.पी-1 के तहत वाजिब दावा निष्पादित किया और कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दिया गया। बेशक, 15-10-1952 को वाजिब दावा प्र.पी. 1 निष्पादित करने की तिथि पर, अब्दुल रज़्ज़ाक को रैयती अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, यह राजस्व मामले संख्या 6 अ/1952-53 में पारित उपायुक्त (भूमि अभिलेख) के 30-10-1954 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अब्दुल रज़्ज़ाक को उनके छोटे भाई रहमत अली के पक्ष में दिनांक 15-10-1952 को वाजिब दावा प्र.पी. 1 निष्पादित करने की तिथि पर रैयती अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए, मुस्लिम कानून के मुल्ला के सिद्धांतों की धारा 54 के आधार पर, मुस्लिम कानून के नियम के तहत विशेष उत्तराधिकार के अधिकार को हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसलिए, प्र.पी. 1 के अनुसार वादी के पिता (रहमत अली) और उसके बाद वादी को कोई शीर्षक प्रदान नहीं किया गया है।

18. उपरोक्त दलील पर विचार करने के लिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6(क) पर गौर करना उचित होगा, जिसे इसके अध्याय ॥ में शामिल किया गया है। धारा 6 में प्रावधान है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति अंतरण किया जा सकता है, सिवाय खंड (क) से (i) में अन्यथा प्रावधान के। धारा 6 का खंड (क) यहां प्रासंगिक है और इसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

> "**6. क्या अंतरित किया जा सकेगा** – कसी भी किस्म की सम्पत्ति इस अधिनियम या किसी भी अन्य तत्समय प्रवृत विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अंतरित की जा सकेगी।
>
> (क) किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की सम्भावना, कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत–संपदा अभिप्राप्त करने की संभावनाया इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती,

19. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 (क) के प्रावधान को उक्त अधिनियम की धारा 2 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अधिनियमितियों, घटनाओं, अधिकारों, दायित्वों आदि को बचाने का प्रावधान करता है। यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि अधिनियम के दूसरे अध्याय (अध्याय ॥) में कुछ भी मुस्लिम कानून के किसी भी नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. सर दिनशॉ फरदुनजी मुल्ला द्वारा लिखित मुल्ला के मुस्लिम कानून के सिद्धांत (20वां संस्करण) का अध्याय 6 मुस्लिम कानून के तहत विरासत के सामान्य नियमों से संबंधित है। अध्याय 6 के अंतर्गत आने वाली धारा 54 में विशिष्ट उत्तराधिकार के हस्तांतरण का प्रावधान है:

उत्तराधिकार के अवसर का त्याग। इसमें निम्नानुसार प्रावधान है: –

> "**§54. विशिष्ट उत्तराधिकार का हस्तांतरण है**: उत्तराधिकार के अवसर का त्याग एक मुसलमान उत्तराधिकारी के संपत्ति में सफल होने का अवसर वैध हस्तांतरण या रिलीज का विषय नहीं हो सकता है।"

21. मोहम्मडन कानून का उपरोक्त नियम कि कोई उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकार के अधिकार को त्याग नहीं सकता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 (क) के तहत कानून से अलग नहीं है।

22. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 (क) में प्रावधान है कि किसी उत्तराधिकारी द्वारा संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त करने की संभावना, किसी संबंधी की मृत्यु पर किसी रिश्तेदार द्वारा विरासत प्राप्त करने की संभावना, या इसी प्रकार की कोई अन्य संभावना को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

23. **<u>गुलाम अब्बास बनाम हाजी कय्यूम अली एवं अन्य</u>**[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला के मोहमडन कानून के सिद्धांतों की धारा 54 को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6(क) के साथ पढ़ते हुए माना कि किसी संपत्ति में भविष्य के हिस्से के संबंध में प्रत्याशा का त्याग उस प्रकरण में जहां पार्टी संबंधित व्यक्ति ने स्वयं पहले के विचारों से अलग होने का निर्णय लिया, जो न केवल संभव था, बल्कि कानूनी रूप से वैध भी था। माननीय न्यायाधीशों ने इस पर निम्न टिप्पणी की: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "12. जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, जबकि मद्रास का दृष्टिकोण इस गलत धारणा पर आधारित है कि भविष्य में उत्तराधिकार के दावे का त्याग करना अपने आप में मुस्लिम कानून द्वारा अवैध या निषिद्ध है, सुलेमान, सीजे द्वारा लताफत हुसैन के मामले (सुप्रा) में व्यक्त किया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, जबकि पूरी तरह से मान्यता देता है कि "मुस्लिम कानून के तहत किसी ऐसे उत्तराधिकारी द्वारा त्याग, जिसका अपने पूर्वज के जीवनकाल में कोई हित नहीं है, अमान्य और शून्य है", सही ढंग से निर्धारित करता है कि ऐसा त्याग, फिर भी, आचरण के एक ऐसे तरीके का हिस्सा हो सकता है जो उस समय अधिकार का दावा करने के विरुद्ध एक बाधा पैदा कर सकता है जब उत्तराधिकार का अधिकार अर्जित हो चुका हो। आसा बीवी के मामले (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय के 5 (1973) 1 एससीसी 1 की पूर्ण पीठ सहित कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, सुलेमान, सीजे ने पृष्ठ 575 पर टिप्पणी की:
>
> > "विबंधन का प्रश्न वास्तव में संविदा अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उठने वाला प्रश्न है, तथा यह मुस्लिम कानून के अंतर्गत सख्ती से उठने वाला प्रश्न नहीं है।"

उन्होंने बताया (पृष्ठ 575–576 पर) :

> "इस न्यायालय में यह माना गया है कि संभाव्य उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए ऐसे अनुबंध, जो किसी प्रतिफल के बदले में हों, उन्हें उस स्थिति में बाध्यकारी माना जा सकता है जब वे वास्तव में संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं: 9 एएलजे 799, और 21 एएलजे 235 देखें। 24 एएलजे 873 में, पृष्ठ 876–77 पर यह बताया गया था कि विचार के लिए एक अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे उन पर

[5] (1973) 1 SCC 1

बाध्यकारी माना जा सकता है यदि वे वास्तव में संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं: 19 एएलजे 799, और 21 एएलजे 235 देखें। 24 एएलजे 873 में, पृष्ठ 876–77 पर यह बताया गया था कि हालांकि संभाव्य अधिकार हस्तांतरण का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह के हस्तांतरण को धारा 6, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम द्वारा निषिद्ध किया गया है, लेकिन भाव्य उत्तराधिकारी को ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे वह अपने आचरण से बाद में उस संपत्ति का दावा करने से खुद को रोक सके, जिस पर वह उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कर सकता है। अन्य मामलों में 40 ऑल 487 में प्रिवी काउंसिल के लॉर्डशिप की घोषणा पर भरोसा किया गया, जहां एक संभाव्य उत्तराधिकारी को एक समझौते से बाध्य माना जाता था, जिसका वह एक पक्ष था।"

13. संयोगवश, हम देख सकते हैं कि मोहम्मद अली खान बनाम बिसार अली खान[6] में अवध मुख्य न्यायालय ने हुरमूत–ऊल–निसा बगुम के प्रकरण (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए कहा था कि "मुस्लिम कानून के अनुसार उत्तराधिकार के अधिकार का त्याग किया जा सकता है और ऐसा त्याग स्पष्ट रूप से होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी अन्य के विरुद्ध बनाए रखने योग्य दावे पर वाद चलाने से रोकने या विरत रहने से निहित हो सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इसी प्रकार, **जुम्मा मस्जिद, मर्करा बनाम कोडिमानियनद्र देविया और अन्य**[7] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया: –

"18. ... तदनुसार हम मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति यह कहते हुए संपत्ति हस्तांतरित करता है कि उसका उसमें वर्तमान हित है, जबकि वास्तव में उसके पास केवल विशेष उत्तराधिकार है, तो हस्तांतरित व्यक्ति धारा 43 के लाभ प्राप्त करने का हकदार है, यदि उसने उस प्रतिनिधित्व के विश्वास पर और प्रतिफल के लिए हस्तांतरण किया है। वर्तमान प्रकरण में, एक्स. III में विक्रेता, संथप्पा ने दर्शाया किया कि वह वर्तमान में संपत्ति पर अधिकार प्राप्त है और यह पाया गया है कि क्रेता ने उस प्रतिनिधित्व पर कार्य करते हुए लेनदेन में प्रवेश किया था, इसलिए उसने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 के तहत संपत्तियों का स्वामित्व हासिल कर लिया, ..."

25. **गुलाम अब्बास** (सुप्रा) में निर्धारित विधि के सिद्धांतों पर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा **शेहम्मल बनाम हसन खानी रावथर एवं अन्य**[8] के मामले में विचार किया गया, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों द्वारा पैराग्राफ 25 में निम्नलिखित तीन प्रश्न तैयार किए गए: –

"(i) क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 और मुल्ला के मुस्लिम कानून के सिद्धांतों की धारा 54 में निहित स्पेस उत्तराधिकार के सिद्धांत के मद्देनजर, एक संभावित उत्तराधिकारी द्वारा निष्पादित त्याग का कार्य उस दावे के

6 AIR 1928 Oudh 67
7 AIR 1962 SC 847
8 (2011) 9 SCC 223

लिए एस्टॉपेल के रूप में कार्य कर सकता है, जिसे संपत्ति के मालिक की मृत्यु पर उत्तराधिकार खुलने के बाद ऐसे कार्य के निष्पादक द्वारा स्थापित किया जा सकता है?

(ii) क्या ऐसे भावी हिस्से के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने के बाद त्याग–पत्र के निष्पादन पर, भावी उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है?

(iii) क्या कोई मुसलमान पारिवारिक समझौते के माध्यम से अपने विशिष्ट उत्तराधिकार के अधिकार को त्याग सकता है, जबकि उसने अभी तक संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं किया है?

माननीय न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 27, 28 और 29 में निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"27. उपरोक्त सामान्य कानून और व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों के बावजूद, न्यायालयों ने यह माना है कि इन प्रावधानों के तहत लगाए गए प्रतिबंध कुछ विशेष परिस्थितियों में हटाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में दो उदाहरण हैं –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) जब कोई संभावित उत्तराधिकारी जानबूझकर कुछ ऐसा करता है, जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के प्रावधानों को आकर्षित करने का प्रभाव पड़ता है, तो क्या उसे संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 (क) के तहत प्रदान किए गए स्पेस उत्तराधिकार के सिद्धांत का लाभ लेने से रोक दिया जाता है, और साथ ही मुस्लिम कानून के तहत मुल्ला के मुस्लिम कानून के सिद्धांतों की धारा 54 में सन्निहित है?

(ii) जब कोई मुसलमान किसी पारिवारिक व्यवस्था में पक्ष बन जाता है, तो क्या इसका यह भी अर्थ है कि वह अपने विशिष्ट उत्तराधिकार के अधिकार को भी त्याग देता है?

उक्त दोनों प्रस्तावों का उत्तर पैरा 25 में पूर्व में तैयार किए गए प्रश्नों का भी उत्तर है।

28. मोहम्मदन कानून स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में यह आदेश देता है कि किसी संपत्ति पर किसी मोहम्मदन उत्तराधिकारी के उत्तराधिकार का अवसर वैध हस्तांतरण या रिहाई का विषय नहीं हो सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6(क) को मोहम्मदनों के बीच प्रचलित प्रथागत कानून और उत्तराधिकार के कानून के सम्मान मे अधिनियमित किया गया था।

29. इसके विपरीत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में निहित सामान्य निरोध के सिद्धांत और संपत्ति में भविष्य के हिस्से के संबंध में त्याग के सिद्धांत हैं। दोनों सिद्धांत उस स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ एक संभावित उत्तराधिकारी ऐसा आचरण करता है या ऐसे कार्य करता है जिससे उपरोक्त दोनों सिद्धांत लागू हो जाते हैं, भले ही मोहम्मदन विधि में त्याग की स्पष्ट अवधारणा हो, जैसा कि मुल्ला की मोहम्मदन विधि के सिद्धांत की धारा 54 में उल्लेखित है।

अंत में, माननीय न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 36 में निम्नानुसार निर्णय दिया: –

> "36. हालाँकि, हम यह स्वीकार करे के लिए इच्छुक नहीं हैं कि मीरालवा रॉथर द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को सख्ती से पारिवारिक व्यवस्था कहा जा सकता है। पारिवारिक व्यवस्था का अर्थ अनिवार्य रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय होगा, न कि परिवार के दो व्यक्तियों के बीच। मीरालवा रॉथर के पाँच बेटों और बेटियों द्वारा निष्पादित किए गए पाँच हक़ त्याग व्यक्तिगत समझौते हैं, जो मीरलावा रावत और संभावित उत्तराधिकारियों के बीच किए गये थे। हालाँकि, उपरोक्त के बावजूद, जैसा कि हमने पहले माना है, निरोध का सिद्धांत आकर्षित होता है ताकि किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों को त्याग के लिए लाभ प्राप्त करने और फिर भी बाद में उसी अधिकार का वाद लाने से रोका जा सके। हमारे विचार में, लोक नीति के विपरीत होने के कारण, उत्तराधिकारी को सामान्य कानून के तहत मृतक की संपत्ति में हिस्सा लेने से रोका जाएगा, जैसा कि गुलाम अब्बास मामले (सुप्रा) में माना गया था।"

26. गुलाम अब्बास (सुप्रा) और शेहम्मल (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि अब्दुल रज्ज़ाक द्वारा वादी संख्या 1 और 2 के पिता रहमत अली के पक्ष में निष्पादित वाजिब दावा (प्र.पी. 1) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 (ए) के साथ मुल्ला के मुस्लिम कानून के सिद्धांतों की धारा 54 के अंतर्गत आता है। तदनुसार, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिवादीगण के विरुद्ध और वादी के पक्ष में दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अब प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादीगण को वादी के गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर बंद करने में विचारण न्यायालय का निर्णय उचित था?

28. विचारण न्यायालय ने वादी के साक्ष्य के लिए 12–7–2002 की तारीख तय की। उक्त तिथि को वादी के पांच गवाह अफजल अली (पीडब्लू–1), सुखदेव (पीडब्लू–2), बिगन साई (पीडब्लू–3), मोहम्मद नईम (पीडब्लू–4) और मोहम्मद सफीक (पीडब्लू–5) उपस्थित थे। जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो न तो प्रतिवादी और न ही उनके वकील उपस्थित हुए और जब बाद में मामले को सुनवाई के लिए लाया गया, तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनके वकील श्री आरए तिवारी, एडवोकेट बाहर गए हैं और इसलिए जिरह स्थगित कर दी जाए, लेकिन विचारण न्यायालय ने मामले को स्थगित करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं पाते हुए स्थगन देने से इनकार कर दिया। आवेदन संख्या 1 का

ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, सिवाय यह दर्शाने के कि उनके वकील श्री आर.ए. तिवारी, अधिवक्ता, बाहर गए हैं, उनके बाहर जाने की दलील के अलावा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और उक्त आवेदन में कोई भी कारण नहीं बताया गया है जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया और वादी के पांच गवाहों की जांच की और प्रतिवादी संख्या 1 जांच के समय पूरे समय मौजूद रहा। इसके बाद, 31–7–2002 को प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के गवाहों से जिरह करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दिया गया और उसे भी विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को स्थगन न देने के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं, क्योंकि आवेदन में केवल यह उल्लेख किया गया था कि श्री आर.ए. तिवारी, अधिवक्ता, बाहर गए थे और वे कहाँ गए थे या उनके अचानक बाहर जाने का कारण या कोई अन्य तात्कालिकता के बारे में कोई और विवरण उक्त आवेदन में नहीं दिखाया गया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को स्थगन मांगने के लिए पर्याप्त कारण बताना चाहिए था, खासकर जब 26–6–2002 को 12–7–2002 के लिए तारीख पहले से ही तय की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा बताए गए कारण पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। स्थगन को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में आवेदन को सही तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अब प्रश्न यह है कि क्या वाजिब दावा (प्र.पी.–1) रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के साथ धारा 49 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के अभाव में साक्ष्य के रूप में अग्राह्य है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(ख) में निम्नानुसार प्रावधान है: –

> "**17. दस्तावेजें जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है** – (1) निम्नलिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करनी होगी यदि वह सम्पत्ति, जिससे उनका सम्बन्ध है, ऐसे जिले में स्थित है, जिसमें और यदि वे दस्तावेजें उस तारीख को या के पश्चात् निष्पादित हुई हैं, जिसको, 1864 का अधिनियम सं. 16 या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1866 (1866 का 20) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1871 (1871 का 8) या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 1877 का 3) या यह अधिनियम प्रवर्तन में आया था या आता है, अर्थात्–
>
> (क) xxx xxx xxx
>
> (ख) अन्य निर्वसीयती लिखत जिनसे यह तात्पर्यित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति में एक सौ रुपये या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हि S. 189 चाहे वह निहित, चाहे समाश्रित हो,

चाहे वर्तमान में करती चाहे भविष्य में सृष्ट घोषित, समनुदेशित परिसीमित या निर्वापित हो,

(ग) से (ड) xxx xxx xxx"

30. प्रश्न यह है कि क्या मुस्लिम वारिस के अवसर को त्यागने के लिए किए गए किसी विलेख को पंजीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि मुस्लिम कानून के मुल्ला के सिद्धांतों की धारा 54 के तहत ऐसा करना बाधित है। मुस्लिम कानून के तहत, एक मात्र संभावना, जैसे कि उत्तराधिकारी के प्रत्याशित अधिकार को वर्तमान या निहित हित नहीं माना जाता है और उत्तराधिकार, वसीयत या हस्तांतरण द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि अधिकार वास्तव में वर्तमान मालिक की मृत्यु से अस्तित्व में नहीं आया हो।

31. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **अब्दुल बनाम गुलाम**[9] के प्रकरण में माना है कि किसी मुसलमान उत्तराधिकारी को संपत्ति का अधिकार देने या उसे त्यागने का दावा करने वाले दस्तावेज को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. इसी प्रकार, लाहौर उच्च न्यायालय ने **नंद लाल बनाम माउंट लखमी और अन्य**[10] के प्रकरण में, है कि प्रत्यावर्तन अधिकारों का हस्तांतरण संपत्ति के हस्तांतरण के समान नहीं है और प्रत्यावर्तनकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावर्तन अधिकारों को छोड़ने के लिए समझौते को शामिल करने वाले दस्तावेज़ के मामले में पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

33. यह स्पष्ट है कि मुस्लिम वारिस को संपत्ति में उत्तराधिकार का मौका देने या उसे सौंपने का दावा करने वाला रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के साथ धारा 49 के तहत पंजीकृत नहीं है। इसका कारण यह है कि वारिस के पास केवल एक विशेष उत्तराधिकार या उत्तराधिकार का मौका होता है, और उसे निहित या आकस्मिक संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं होता है। इसलिए, ऐसा दस्तावेज़ वैध नहीं है को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और यह रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(ख) के अर्थ में निहित या आकस्मिक अधिकार के समान नहीं होगा।

---

9 (1905) 30 Bom 304
10 AIR 1939 Lahore 414

34. उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर, मेरी यह राय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निरस्त करना पूरी तरह से अनुचित है। परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निरस्त किया जाता है और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाता है। अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

35. तदनुसार डिक्री तैयार की जाएगी।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur